RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शनिवार 06 जनवरी 2023 वर्ष 05 अंक 254 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

ठाणे में अपार्टमेंट में बुजुर्ग दंपति मृत पाए गए...

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे शहर के एक अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग दंपति मृत पाए गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि शमशेर बहादुर सिंह (68) और उनकी पत्नी मीना (65) के शव चितलसर इलाके में उनके फ्लैट में मिले। शव उनके बेटे ने देखे जो बृहस्पतिवार सुबह से फोन कॉल का जवाब नहीं मिलने के बाद फ्लैट में पहुंचा था। उन्होंने बताया कि दंपति की मौत बुधवार और बृहस्पतिवार की दरमियानी रात हुई हैं। अधिकारी के अनुसार, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शवों पर चोट के निशान नहीं है और उन्हें जहर देने का संदेह है। उन्होंने बताया कि सिंह एक सुरक्षाकर्मी का काम करता था और उनकी पत्नी घर से ही एक छोटा व्यवसाय चलाती थी।

मंच पर मौजूद थे अजित पवार

बीजेपी विधायक सुनील कांबले ने मारा पुलिसवाले और NCP नेता को थप्पड़

पुणेः बीजेपी विधायक सुनील कांबले पर एक पुलिस अधिकारी और एनसीपी के मेडिकल सेल प्रमुख के साथ मारपीट का आरोप है। यह सब ससून अस्पताल में अजीत पवार के निरीक्षण के दौरान हुआ। मंच पर कार्यक्रम चल रहा था। इस प्रोग्राम में डेप्युटी सीएम अजित पवार मंच पर थे। इसी दौरान सुनील कांबले मंच से नीचे उतर रहे थे। अचानक सीढ़ियों पर उनका पैर फिसला और वह गिरने से बचे। उन्होंने इसका गुस्सा पास खड़े पुलिसकर्मी पर निकाला और उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। यह भी कहा जा रहा है कि सुनील कांबले मंच पर उन्हें प्राथमिकता न दिए जाने से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने अपना फ्रशटेशन पुलिसकर्मी पर उतारा। उसके बाद एनसीपी के नेता पर गुस्सा हुए। सारी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायर हुआ तो सुनील कांबले चौतरफा हमले शुरू हो गए। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार आज सुबह से ही पुणे में विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं। उनका पुणे में सरकार के संचालित ससून अस्पताल में विभिन्न वार्डों का उद्घाटन करने का कार्यक्रम था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अजीत पवार के समर्थक भी उपस्थित थे।

सुनील कांबले ने दी सफाई...

जब विधायक सुनील कांबले से ऑफ रिकॉर्ड पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें वहां मारा गया। उन्होंने कहा, 'उसने मुझे दो-तीन बार धक्का मारा। तो मुझे गुस्सा आ गया। उसे मैंने दो से तीन बार मना भी किया लेकिन उसने नहीं सुना, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा।' सुनील कांबले ने कहा, 'उपमुख्यमंत्री अजीत पवार हमारे नेता हैं। चूंकि वह ससून अस्पताल में काम का निरीक्षण करेंगे, इसलिए मैं पिछले सात दिनों से इस ससून अस्पताल में काम का निरीक्षण और समीक्षा कर रहा हूं। मैं तनाव में था।'

शरद पवार के पोते की कंपनी में ED की रेड

महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मामले में कार्रवाई

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बारामती एग्रो कंपनी के परिसर में छापेमारी की। यह कंपनी राकांपा प्रमुख शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार की है। बारामती, पुणे, औरंगाबाद और अमरावती के छह इलाकों में छापेमारी की गई। यह मामला 2019 में प्रकाश में आया जब मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई थी। इस छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने भाजपा पर निशाना साधा है। राकांपा प्रमुख ने कहा कि उसके विधायक रोहित पवार की हाल ही में संपन्न हुई 'युवा संघर्ष यात्रा' ने भाजपा के लिए असुरक्षा की भावना पैदा की है।

राकांपा के प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने कहा, 'केंद्रीय एजेंसी की ये छापेमारी अहमदनगर जिले के कर्जत-जामखेड से पहली बार विधायक बने रोहित पवार को नहीं रोक पाएगी। वह पहले से ज्यादा मजबूत बनकर आएंगे। इससे साबित होता है कि संघर्ष यात्रा ने भाजपा को आघात किया है।' वहीं भाजपा नेता कीरित सोमैया ने इस मामले में जल्द से जल्द जांच की मांग की है।

खेरवाड़ी पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस इंस्पेक्टर के साथ सायबर ठगी

केवायसी अपडेट करने के नाम पर धोखाधड़ी

मुंबई : खेरवाड़ी पुलिस थाने में कार्यरत एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ सायबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इंस्पेक्टर की शिकायत पर खेरवाड़ी पुलिस थाने में ही दो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। केवायसी अपडेट करने के नाम पर पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिस इंस्पेक्टर के साथ धोखाधड़ी हुई है उनका नाम हेमंत गुरव (51) है। गुरव खेरवाड़ी में इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं। 3 जनवरी के दिन उन्हें एक फोन कॉल आया और कॉल करनेवाले ने बताया कि वह एक्सिस बैंक से बोल रहा है, उनकी केवायसी अपडेट करनी होगी। अगर वे अपडेट नहीं कर पाए तो आनेवाले समय में समस्या होगी। इनका अकाउंट उसी बैंक में था जहां से गृह ककरज चल रहा था।

माहिम मेला रविवार 07 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा, मेला 12 दिनों का होगा ?

माहिम : हजरत मखदूम शाह बाबा का मेला 27 दिसंबर को मुंबई पुलिस कि सलामी फिर संदल के साथ चददर पेश करने से शुरू हुआ और खत्म 05 जनवरी को होना था मेला 10 दिनों का होता है अब पुलिस 12 दिनों का करने का निर्णय लिया है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब मेले का आखिरी दिन 07 जनवरी होगा । हजरत मखदूम शाह बाबा का मेला 2 हिस्सो में है एक हिस्सा दरगाह शरीफ और खाओ गल्ली है माहिम दरगाह ट्रस्ट देखती है और दूसरा हिस्सा रहती बंदर का है जहा झूले और खाने पीने की दुकान लगती है जो झूले वाले चलाते है कलेक्टर, पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पुलिस सब मिलाके 25 के आसपास परमिशन लेखे इस साल माहिम पुलिस स्टेशन के वरिष्ट पुलिस इंस्पेक्टर शिरसत ने मेले वालो को शौगत दी है झूले का बंद करने का समय रात 12 बजे किया था अब 10 दिन के बदले 12 दिन करने का फैसला किया है । दरगाह शरीफ शनीचर यानी 6 जनवरी से अपने रोजाना वक़्त 10 बजे से मालूम होगी जो मेले के समय रात 1.30 बजे बंद होती थी ।

मुलुंड-ठाणे के बीच बनेगा नया स्टेशन पूरा होगा 2025 तक...

मुंबई : स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मुलुंड और ठाणे के बीच निमार्णाधीन ठाणे स्टेशन विस्तार पर काम जोरों पर है। स्टेशनों को जोड़ने वाली तीनों एलिवेटेड सड़कों के बीच 1 सड़क का काम तेजी से चल रहा है और बाकी 2 सड़कों का काम भी जल्द ही तेज हो जाएगा. ठाणे नगर पालिका और रेलवे प्रशासन के बीच एमओयू की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो विस्तारित ठाणे स्टेशन दिसंबर 2025 तक यात्रियों के लिए तैयार हो जाएगा। मार्च 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने परिसर के हस्तांतरण पर लगी रोक हटा दी। इसके बाद ठाणे और मुलुंड स्टेशनों के बीच मनोरोग अस्पताल पर प्रस्तावित विस्तारित ठाणे रेलवे स्टेशन बनाया गया। अप्रैल में राज्य सरकार ने अस्पताल के लिए नगर पालिका को 14.83 एकड़ जमीन निःशुल्क हस्तांतरित की थी। ठाणे स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए अस्पताल की जगह नया स्टेशन विकसित किया जा रहा है। ठाणे स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 7. 5 लाख लोग आते-जाते हैं. इसके लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 144.80 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. विस्तारित ठाणे स्टेशन वागले एस्टेट सहित घोड़बंदर परिसर के लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। अस्पताल के महिला वार्ड को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया. दिसंबर से अब तक प्रोजेक्ट का करीब 22 फीसदी काम पूरा हो चुका है. एसएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कर रही है काम विस्तारित ठाणे स्टेशन पर तीन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे।

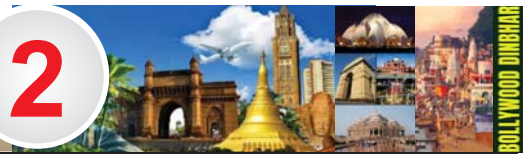

संपादकीय / लेख

नए आदेशों में सीपीएस

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

सरकार के कार्य, सरकार की दक्षता और सत्ता में हिस्सेदारी के फलक पर मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर आया हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश अपने आप में कई अर्थ लिए है। आदेश की पलकों पर सवार होकर भाजपा खुशियां मना सकती है, लेकिन सरकार की ये नियुक्तियां अभी यथावत हैं तो इसलिए कि माननीय अदालत ने इसके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। यानी बिना मंत्री पद की सुविधाओं, शक्तियों और भत्तों के अगर जहाज उड़ रहे हैं, तो सियासी फिजा में फिलहाल कोई खतरा नहीं। फैसले की वजह अभी बाकी है और निष्कर्षों का सामान भी। सरकार के गठन में सियासी संतुलन और क्षेत्रीय महत्त्वाकाक्षाओं के रथ पर सवार ऐसे पद पहले भी विवादित रहे हैं तथा कानूनी तौर पर एक पक्ष इनके खिलाफ रहा। सरकारों की अमानत में ऐसी नियुक्तियों का ढहना भी विरोध की सियासत का उठना है। ऐसे में बहुप्रतीक्षित फैसले के निर्देश भले ही सख्त हैं, लेकिन बारह मार्च तक कई नेताओं के सम्मान बरकरार हैं। निर्णय के दूसरी ओर भाजपा के लिए यह नैतिकता के प्रश्न पर कानूनी इबारत है जो उसके विरोध व कानूनी लड़ाई को एक आयाम तक पहुंचा रही है। सीधे तौर पर जिस जश्न की फिराक में सत्ता के रंग कमोबेश मंत्रियों की पोशाक में मुख्य संसदीय सचिवों को सुशोभित कर रहे थे, वहां एक विराम सी खामोशी दे गई। वैसे भी सरकार के व्यवहार में अग्रणी होने की ख्वाहिश सत्ता पक्ष के विधायकों में रहती है। सीपीएस बन कर मंत्री सरीखा प्रोटोकोल, प्रशासनिक पहुंच तथा मीडिया संवाद में सरकार की व्याख्या करते नेता क्या अब शांत हो जाएंगे। इनके पास बाकायदा विभागों के दायित्व और सरकार के महकमों का नूर भी चलता रहा है, तो क्या अब मुख्य संसदीय सचिव का पद सिर्फ एक विधायक का तमगा या सरकार के बागीचे का महज एक फूल है।

वित्तीय शक्तियों के तराजू भले ही अदालत ने बांध दिए या सरकार की ओर स्पष्ट किया गया है कि ये पद मंत्रियों की तरह नहीं नवाजे गए, लेकिन व्यावहारिकता में अब भी भाजपा की नुक्ताचीनी में सीपीएस महोदयों पर विपक्ष की निगरानी रहेगी। अंतिम फैसले की आहट कितनी गंभीरता से अब मुआयना करेगी, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ अंकुश जरूर लगेगा सत्ता के इस सफर पर। यह इसलिए भी कि अंतरिम फैसला सत्ता के इन पदों की देह भाषा बदलेगा। अब तक की परिस्थितियों में अदालत के निर्देश नहीं थे, जबकि आइंदा विपक्ष अपने विरोध के जज्बात लिए फैसले की नसीहत में निगरानी करने में चूक नहीं दिखाएगा। हालांकि मोटे तौर पर ऐसी कानूनी लड़ाइयों से न तो राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ रही है और न ही सरकारों के अपव्यय रुक रहे हैं। हिमाचल का ही संदर्भ रखें, तो फिजूलखर्ची के आलम में कर्ज की कोई सीमा नहीं रही। न सरकारों के आकार और न ही प्रकार में कोई अंतर आया। अब केवल मंत्रिमंडल या बोर्ड-निगमों का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद तक ही सरकार का आकार नहीं। अगर मंत्रिमंडल के सदस्यों की सीमारेखा तय है, तो सत्ता की किश्तियों पर अन्य कई धुरंधर सवार हो सकते हैं। काबीना मंत्री का पद न सही, कैबिनट रैंक से कोई भी सुशोभित हो सकता है। ऐसे में भाजपा के बारह विधायकों की मन्नत अगर कांग्रेस के छह विधायकों से रुतबा छीन रही है, तो भी यह संकल्प अधूरा और एकलक्षीय है। हिमाचल के अर्थतंत्र में नैतिकता के ऐसे कई सवाल हैं, जिनके ऊपर न विपक्ष कुछ बोलता और न ही सत्ता में आते कोई दल इनसे जूझता है। सुक्खू सरकार ने भी आत्मनिर्भरता के नारे में प्रदेश की आर्थिक स्थिति के उत्थान की कसम खाई है, लेकिन यथार्थ में फिजूलखर्ची पर कहीं अंकुश दिखाई नहीं देता। प्रदेश में कई अनावश्यक विभाग, निगम, बोर्ड, शिक्षण चिकित्सा संस्थान व दफ्तर हैं जिनके दरवाजे सदा सदा के लिए बंद कर देने चाहिएं। बेशक सुक्खू सरकार ने आते ही डिनोटिफिकेशन के साथ अलार्म बजा कर पिछली सरकार के अंतिम दौर की घोषणाओं को घूंघट में बंद किया, लेकिन असली मर्ज के लिए यही एक दवा नहीं। सरकार को अपने आकार में भी आदर्श स्थापित करने होंगे। हिमाचल को अब आर्थिक अनुशासन, बेहतर प्रशासन व बजटीय आश्वासन को मुकम्मल करना होगा। मिशन रिपीट, रिवाज बदलेंगे या कर्मचारियों पर भाषण देने के बजाय, राज्य की बेहतरी के लिए संसाधनों के सृजन और अपने भौगोलिक व प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने की आदत डाल लेनी चाहिए। सत्ता के नर्म गद्दों पर तो हर कोई बैठना चाहता है, लेकिन प्रदेश के कांटों को बटोरने का सामर्थ्य जब तक पैदा नहीं होगा, कोई क्रांति नहीं आएगी।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

केंद्र सरकार जिस स्कीम का कर रही विरोध उसी को बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार क्यों कर रही लागू?

मुंबईः पिछले काफी समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग तेज होती जा रही है। सरकार पर दवाब बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी कई प्रदेशों में धरना-प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने शुरू से ही साफ कर दिया है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई। इन सभी राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने ओपीएस स्कीम

लागू की थी। लेकिन अब महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाली शिंदे सरकार भी 26 हजार कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने जा रही है। केंद्र सरकार जिस ओल्ड पेंशन का विरोध करती आ रही है, वहीं स्कीम बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार लागू कर रही है। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां बीजेपी गठबंधन वाली सरकार कुछ सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने जा रही हो। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही जो महाराष्ट्र सरकार इन सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने जा रही है।

दरअसल सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग लगातार बनी हुई है। इस पर कर्मचारियों का विरोध लगातार चल रहा है। मराठा आरक्षण पर घिरी शिंदे सरकार अब कोई और रिस्क लेना नहीं चाहती। सरकार अब इसे लेकर दबाव भी महसूस करने लगी है। इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में शिंदे सरकार ने 26 हजार सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में ला रही है। बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है।

शिंदे सरकार ने लिया ये फैसला

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने 1 नवंबर 2005 के दिन या उसके पहले सरकारी नौकरी जॉइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया है। पिछले महीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कर्मचारियों को बजट से पहले पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का भरोसा दिलाया था। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के 26000 कर्मचारियों को फायदा होगा। इन कर्मचारियों की नियुक्ति नवंबर 2005 से पहले हुई थी, लेकिन जॉइनिंग नवंबर 2005 के बाद हुई थी। नवंबर 2005 से पहले राज्य सरकार में तकरीबन साढ़े नौ लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, जो पहले से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ पा रहे हैं।

केंद्र सरकार का रुख साफ...

केंद्र सरकार की बात करें तो उसने पहले ही साफ कर दिया है कि उसकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा था कि एक जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई थी जो एक अप्रैल, 2004 से प्रभावी है।

महाराष्ट्र में इस साल छह सांसदों का कार्यकाल हो रहा खत्म!

लिस्ट में इन दिग्गजों का नाम शामिल

मुंबई : नौ केंद्रीय मंत्रियों समेत राज्यसभा के 68 सदस्यों का कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है. इसलिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच घमासान अभी से शुरू हो गया है. इन 68 रिक्तियों में से दिल्ली की तीन सीटों पर चुनाव की घोषणा पहले ही हो चुकी है. सिक्किम की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 57 नेता अप्रैल में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश में खाली होंगी. उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार में छह-छह, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पांच-पांच, कर्नाटक, गुजरात में चार-चार, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश में तीन-तीन, झारखंड, राजस्थान में दो-दो, उत्तराखंड में एक-एक और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से 1-1 सीटें खाली होगी. बीजेपी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं लेकिन दोबारा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अपने गृह राज्यों से बाहर सीटें तलाशनी होंगी.

महाराष्ट्र से राज्यसभा गए विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कांग्रेस के कुमार केतकर, एनसीपी की वंदना चव्हाण और शिवसेना (यूबीटी) के अनिल देसाई भी अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. बता दें, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था. महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं. राज्य की 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

क्लीनिक में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, डॉक्टर ने पार की हैवानियत की सारी हदें

मुंबई : मुंबई के मलाड स्थित एक क्लीनिक में किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आधिकारिक सूचना के अनुसार गुरुवार को पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। सूचना के मुताबिक डॉक्टर पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। अधिकारी ने बताया कि घटना 28 दिसंबर को उस क्लिनिक में हुई जहां लड़की (उम्र का खुलासा नहीं) काम करती थी। सूचना मिलने के बाद कुरार पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नगर निगम अस्पताल भेज दिया।

इधर, मृतक की मां ने कहा कि

उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है और दावा किया है कि उन्होंने डॉक्टर के अभद्र व्यवहार के बारे में शिकायत की थी। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 376 (बलात्कार के लिए सजा) और किशोर न्याय अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया है। इसके बाद मामले की जांच की जा रही है।

नए साल की शुरूआत प्रदूषित हवा में... बदलापुर में पहले तीन दिनों में हवा की गुणवत्ता खराब हुई

बदलापुरः पिछले साल के आखिरी कुछ महीनों में मुंबई और उसके उपनगरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई थी. हालांकि, नए साल की शुरूआत में भी यह बात सामने आई है कि ठाणे जिले के ठाणे, बदलापुर, उल्हासनगर, भिवंडी शहरों में हवा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक, 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच विभिन्न शहरों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 180 से 300 के बीच है। तो नए साल की शुरूआत भी

अशुद्ध हवा के साथ हुई है. पिछले कुछ महीनों में मुंबई, ठाणे और उपनगरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट देखी गई है। हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सड़कों को धोना और उन पर धूल कम करना, निर्माण स्थलों पर विशिष्ट नियमों को लागू करने के लिए मजबूर करना, कचरे और धूल को कम करने के लिए कार्यान्वयन योजनाएं बनाना जैसे काम किए गए। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद सड़कों पर उतर आये हैं और सघन सफाई अभियान चला रहे हैं. इसी तरह के निर्देश ठाणे, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी नगर पालिकाओं को भी दिए गए हैं। कुलगांव बदलापुर और अंबरनाथ जैसी नगर पालिकाओं को भी इसी तरह के नोटिस मिले हैं। हालांकि, इन निदेर्शों का पालन करने के बाद भी जिले में एयर इंडेक्स में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है.

पाम बीच रोड पर 10 करोड़ में मरम्मत का काम शुरू...

माइक्रोसरफेसिंग के जरिए सड़क मरम्मत से बढ़ेगी रफ्तार

नवी मुंबई: फोर्ट गवथन से अरेंजा कॉर्नर तक पाम बीच रोड पर विभिन्न स्थानों पर छोटे पुलों और जंक्शनों की मरम्मत माइक्रोसरफेसिंग द्वारा की जा रही है। इसलिए जगह-जगह क्षतिग्रस्त पाम बीच रोड की मरम्मत का काम शुरू किया जा रहा है और नगर पालिका ने यह काम शुरू भी कर दिया है. इसलिए भविष्य में इस मार्ग पर यातायात और अधिक सुगम होगा। पामबीच मार्ग पर यात्रा करना जहां शहर के युवाओं के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए भी प्राथमिकता है, वहीं शहर के भौतिक विकास के साथ-साथ शहर में पर्याप्त और आकर्षक सुंदरता जोड़ने के लिए नगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगातार सुधार कर रही है। नगर पालिका ने इस एक्सप्रेसवे पर सड़क सुधार का काम शुरू कर दिया है और सिग्नल के पास छोटे पुलों और जंक्शनों के साथ-साथ इस सड़क पर माइक्रो सरफेसिंग का काम किया जा रहा है। पाम बीच रोड पर विभिन्न जंक्शन हैं जो बेलापुर में किल्ले गावथन से शुरू होते हैं और वाशी में अरेन्जा कॉर्नर पर समाप्त होते हैं।

गाड़ियां चोरी कर इंजन नंबर बदलकर देशभर में बेचीं जा रही थी...

सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने अन्तर्राज्यीय गिरोह को किया गिरफ्तार

वसईः सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली से लग्जरी गाड़ियां चुराकर पूरे देश में बेचता था. गाड़ियों के इंजन, चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बदल जाने के कारण यह चोरी संभव नहीं हो पाती थी. लेकिन पुलिस ने तकनीकी जांच कर इस मामले का खुलासा कर दिया. इस गिरोह के पास से चोरी की गई 8 लग्जरी कारें बरामद की गई हैं. सेंट्रल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि लग्जरी गाड़ियों की चोरी

की जा रही है और उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन और चेसिस नंबर बदलकर बेचा जा रहा है. इस मामले में केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक हितेंद्र विखरे को सौंपी गई. पुलिस ने इस मामले में तकनीकी जांच की और एक गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के नाम मिलन राजसिंह उर्फ बापू चौहान (35), गरीफ हुसैन खान (33), इरशाद अजमेरी (39), वसीम पठान (37), शाहिद खान (34), नबीजान उर्फ शौकत अली अंसारी (47) हैं। पुलिस ने इस गैंग के पास से ढाई करोड़ से ज्यादा कीमत की चोरी की 8 गाड़ियां जब्त की हैं. आरोपी के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं।

ऑनलाइन गांजा बेचने वाला गिरफ्तार

मुंबईः नवघर पुलिस ने 21 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पर ग्राहक ढूंढकर गांजा बेच रहा था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा बरामद कर लिया है और पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है. गिरफ्तार युवक का नाम शुभम घाडिगोनकर है और वह मुलुंड के नवघर इलाके में रहता था। दो दिन पहले जब पुलिस नवघर इलाके में वाहनों की जांच कर रही थी, तब शुभम दोपहिया वाहन पर वहां आया। पुलिस ने उसे रुकने की चेतावनी दी. लेकिन वह पुलिस को देखकर भागने लगा. तो पुलिस ने तुरंत उसका पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे हिरासत में ले लिया.

4 जनवरी से 20 मार्च के बीच इम्फाल से शुरू होकर ठाणे में खत्म होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा

मुंबई : कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से महाराष्ट्र तक की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर निकलने वाले हैं. इसके लिए कांग्रेस तैयारियों में जुटी है. इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप जारी कर दिया गया है. रूट मैप के अनुसार यात्रा इम्फाल से शुरू होकर मुंबई के ठाणे में खत्म होगी. अगर बात सिर्फ महाराष्ट्र की करें तो राहुल गांधी की यह यात्रा राज्य में लगभग 5 दिनों तक चलेगी.

रूट मैप के अनुसार महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुल 6 जिलों से होकर गुजरेगी और 479 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. यात्रा मालेगांव से महाराष्ट्र में एंट्री करेगी और नासिक होते हुए ठाणे में जाकर खत्म होगी. भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20

मार्च के 15 राज्यों से होकर जाएगी. इस तरह कुल 6,713 किलोमीटर से अधिक की यात्रा बसों और पैदल तय की जाएगी. इसमें 110 जिले, लगभग 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा क्षेत्र आएंगे. वहीं यात्रा पूरी होने में लगभग 66 दिन लगेंगे.

गौरतलब है कि कांग्रेस ने इस यात्रा का गुरुवार को नाम भी बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया. पहले इसका नाम भारत न्याय यात्रा था. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसकी घोषणा की. रमेश ने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही है और इसके लिए निमंत्रण भेजे जा रहे हैं. रमेश ने दावा किया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीति के लिए उतनी ही परिवर्तनकारी साबित होगी, जितनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा हुई थी. बता दें कि पहले चरण में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों को कवर करते हुए लगभग 4,000 किलोमीटर की यात्रा की थी. भारत के पूर्व से पश्चिम तक की इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले लोगों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही

कोविड सेंटर घोटाले में आदित्य ठाकरे के करीबी पर कसा शिकंजा... जानिए क्या है मामला

मुंबई : महाराष्ट्र में बड़े कोविड सेंटर संचालित करने में हुए कथित घोटाले में मुंबई पुलिस ने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल गोम्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राहुल गोम्स बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर है। आर्थिक अपराध शाखा ने राहुल गोम्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 409, 420 और 120(बी) के तहत मामला दर्ज किया। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार रात मुलुंड और दहीसर में कोरोना काल के दौरान बनाए गए बड़े कोविड सेंटर में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में नई एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस ने बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर राहुल गोम्स की ओक्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी

प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही इसके वेंडर्स और अज्ञात नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ 37 करोड़ रुपये के घोटाले में मामला दर्ज किया है।

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कोरोना के दौरान कोविड सेंटर्स में किए गए कथित घोटाले का मामला उठाया था। आरोप है कि अक्तूबर 2020 से लेकर अगस्त 2022 तक चलाए गए कई बड़े कोविड सेंटर्स के किराए के तौर पर मोटी रकम ली गई और साथ ही झूठे बिल के जरिए वित्तीय गड़बड़ी भी की। आरोप है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और बीएमसी के अधिकारियों ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। इस घोटाले से सरकार को करीब 37 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आर्थिक अपराध शाखा जल्द ही बीएमसी अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स से पूछताछ कर सकती है। राहुल गोम्स की कंपनी ने कोविड सेंटर्स के लिए बेड, पंखे, टेंट और अन्य कई सुविधाएं मुहैया कराईं। राहुल गोम्स की कंपनी ने दहीसर, वर्ली, एमएमआरडीए, मुलुंड और बीकेसी पार्ट 2 में कोविड सेंटर चलाने के लिए सामान की सप्लाई की थी। इससे पहले जुलाई 2023 में ईडी ने भी राहुल गोम्स के ठिकानों पर छापेमारी की थी।

वसई, भायंदर से हर दिन 6 लोग लापता... तलाश में पुलिस की उदासीनता

वसई : वसई विरार और मीरा भायंदर शहर से हर दिन 6 लोग लापता हो रहे हैं। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक ये मामला सामने आया है. पिछले साल के 11 महीनों में 2 हजार 42 लोग लापता हुए. इनमें से 514 लोगों का पता नहीं चल पाया है. विभिन्न कारणों से वसई विरार और मीरा रोड, भायंदर शहर में लोगों के अपने घर छोड़ने के कई मामलों में सामने आई है। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है. साल 2023 में (30 नवंबर तक) 2 हजार 42 लोग लापता हुए. इसमें 1 हजार 162 महिलाएं और 880 पुरुष शामिल हैं। इनमें से 1 हजार 528 लोग घर लौट चुके हैं जबकि 514 लोगों का अभी भी पता नहीं चल

पाया है। यानी हर दिन औसतन 6 लोग लापता होते हैं. लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि पुलिस गुमशुदा लोगों की तलाश में उदासीन रहती है.

18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के लापता होने पर अपहरण का मामला दर्ज किया जाता है. लेकिन 24 घंटे बाद एक वयस्क के लापता होने की सूचना मिली है. लेकिन कई मामलों में ऐसे लापता लोगों की जांच में पुलिस की ढिलाई देखी गई है. नायगांव निवासी नयना महंत (28) 9 अगस्त से लापता थी। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने समय पर जांच नहीं की. बाद में नयना का शव गुजरात के वलसाड में मिला. लेकिन चूँकि वह उस समय बेसहारा था, इसलिए गुजरात पुलिस ने उसका निस्तारण कर दिया। नायगांव की बहन जया महंत ने आरोप लगाया है कि अगर नायगांव पुलिस समय पर जांच करती तो कम से कम हमें मेरी बहन का शव दाह संस्कार के लिए मिल जाता. श्रद्धा वॉकर के लापता होने की रिपोर्ट उसके पिता ने 22 सितंबर 2022 को मानिकपुर थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसकी सूचना मिली. वसई पुलिस ने बिना शिकायत लिए ही उन्हें वापस भेज दिया। इस मामले में मृतक श्रद्धा वॉकर के पिता ने पुलिस की ढिलाई की शिकायत की थी. गृह विभाग ने भी मामले की जांच का निर्देश दिया है. यदि नाबालिग लापता हैं तो अपहरण अपराध सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शानुसार नाबालिग बच्चों के लापता होने पर अपहरण का मामला दर्ज किया जाता है। इनमें से अधिकतर लड़के-लड़कियां प्रेम संबंधों के चलते घर छोड़कर चले गए हैं।

महाराष्ट्र के इन जिलों में अगले दो दिनों में होगी बारिश

मुंबई : मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार और शनिवार को कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के साथ उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव, धुले और नंदुरबार में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। उत्तरी कोंकण से उत्तर दिशा में हवा का एक ट्रफ बना हुआ है। जम्मू से लेकर उत्तरी पाकिस्तान तक एक वेस्टर्न डिफ्लेक्शन (ठंडी हवा की स्थिति) बन गई है, जिससे दक्षिण हरियाणा समेत आसपास के इलाकों में हवा की ऊपरी परत में एक चक्रवाती हवा की स्थिति बन गई है। दक्षिण पूर्व दिशा से आ रही भापयुक्त

हवा के कारण प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। मध्य भारत में उत्तरी ठंडी हवाओं और दक्षिण-पूर्व से आने वाली भाप भरी हवाओं के साथ मध्य भारत, उत्तरी महाराष्ट्र के धुले, जलगांव और नंदुरबार में हल्की बारिश का अनुमान है। जबकि दक्षिण से आने वाली भाप भरी हवाओं के कारण कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश की उम्मीद है।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : शनिवार 06 जनवरी 2023

दिन-ब-दिन बढ़ रही अनधिकृत पार्किंग की समस्या...

सड़क के दोनों ओर दो पहिया... चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं

उरण: नगर पालिका के अनियोजित प्रबंधन के कारण उरण शहर में पार्किंग की समस्या दिन-ब-दिन उत्पन्न होती जा रही है. इसकी वजह से शहर बर्बाद हो गया है.' दोनों सड़कों पर बेतरतीब ढंग से दोपहिया व चारपहिया वाहन खड़े किये जा रहे हैं. साथ ही सड़क पर कहीं भी ठेले लगा दिए जाने से जाम भी लग जाता है। इसके चलते उरांकर मांग कर रहे हैं कि नगर निगम उचित योजना बनाकर पार्किंग की समस्या का समाधान करे. यहां की संकरी सड़क के कारण उरण शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। पिछले पांच साल से शहर की मुख्य सड़कों का कंक्रीटीकरण हो रहा है. शहर की मुख्य सड़कें जैसे चार फाटा से राजपाल नाका, कोट नाका से वैष्णवी होटल तक का निर्माण किया गया है; लेकिन, इन मुख्य सड़कों पर बड़ी संख्या में अनाधिकृत ठेले व ठेले लगाये जा रहे हैं. साथ ही, नागरिकों के फुटपाथों को भी व्यापारियों ने निगल लिया है। इसके अलावा शहर की मुख्य सड़कों के दोनों ओर दोपहिया व चारपहिया वाहन खड़े किये जा रहे हैं. इसके चलते दिन-रात सड़कों पर जाम लगा रहता है। ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका की ओर से सड़क पर सफेद पट्टियां लगाई गई हैं। फिर भी दुकानदार दोनों तरफ अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते हैं।

नगर निगम के नए मुख्यालय के उद्घाटन में देरी...

फर्नीचर और सामग्री में लगने लगा जंग

वसईः साल बीत जाने के बावजूद भी वसई विरार नगर निगम के नए मुख्यालय का उद्घाटन नहीं हो सका है. इसके कारण इस मुख्यालय के कार्यालय का सामान खराब होने लगा है. पुराने मुख्यालय को नये भवन में शीघ्र स्थानांतरित करने की मांग जोर पकड़ रही है. वसई विरार नगर निगम की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। उस समय 4 नगर परिषदें थीं। नगर निगम की स्थापना के बाद निगम का मुख्यालय अस्थायी रूप में विरार नगर परिषद के कार्यालय में शुरू किया गया। लेकिन नगर निगम की स्थापना के 14 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक इसे नया मुख्यालय नहीं मिल सका है.

इस बीच, विरार वेस्ट ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग को मुख्यालय में बदल दिया गया। इस मुख्यालय की पहली दो मंजिलों पर परिवहन भवन का निर्माण किया गया है जबकि तीसरी से सातवीं मंजिल पर मुख्यालय का निर्माण किया गया है। हालांकि, काम पूरा होने के बावजूद नये मुख्यालय में काम शुरू नहीं हो सका है. इसके कारण इस कार्यालय में फर्नीचर व अन्य सामग्री खराब होने लगी है. जल्द से जल्द नए मुख्यालय में शिफ्ट करने की मांग की जा रही है.

मुख्यालय का मूल स्थान इतिशजामा है

नगर पालिका का मुख्य मुख्यालय विरार पश्चिम के बोलिंज में बनाने का निर्णय लिया गया। 2017 में, नगर पालिका ने विरार पश्चिम के विराट नगर में दस एकड़ विशाल भूमि में छह लाख वर्ग मीटर का क्षेत्र भी निर्धारित किया था। भवन की आधारशिला 2017 में तत्कालीन संरक्षक मंत्री विष्णु सावरा, सांसद चिंतामन वनगा के नए मुख्यालय के लिए रखी गई थी। इस मुख्यालय का शिलान्यास उन्हीं के द्वारा किया गया था. इस मुख्यालय की लागत 300 करोड़ रुपये थी. प्रस्तावित मुख्यालय भवन में एक थिएटर, आर्ट गैलरी, वस्तु संग्रहालय, विवाह समारोहों के लिए सभागार, सम्मेलन कक्ष आदि शामिल थे। इसे पांच सितारा होटल की तरह डिजाइन किया गया था और इसे तीन साल में पूरा किया जाना था। इस नए मुख्यालय की अवधारणा नगर पालिका के 2018 दैनिक में प्रकाशित की गई थी। लेकिन अब मुख्यालय का यह मूल स्थान इतिहास संजो चुका है।

मौजूदा कार्यालय में कठिनाई...

नगर पालिका का वर्तमान मुख्यालय विरार नगर परिषद भवन में जारी है। लेकिन वह जगह अपर्याप्त है. लेकिन इस बिल्डिंग में जगह की कमी के कारण इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर सेक्शन बनाए गए हैं। इसलिए नगर पालिका में महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकार्ड रखने से लेकर नगर पालिका में काम के लिए आने वाले नागरिकों को इस समय दिक्कत हो रही है. कभी-कभी नागरिकों को काम के लिए इधर से उधर जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में भी छत से पानी टपकने से परेशानी बढ़ रही है.

नवी मुंबई के स्लम इलाकों में सार्वजनिक शौचालयों के बाहर कतारें...

नवी मुंबई : नवी मुंबई के स्लम इलाकों के कुछ निवासियों ने 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत शौचालय बनाने के लिए सब्सिडी का लाभ उठाया है, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण, कई लोगों को अभी भी सार्वजनिक शौचालयों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी तरह अपर्याप्त शौचालयों के कारण खुले में बैठने वाले लोगों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है. अतः तस्वीर यह है कि अपर्याप्त सार्वजनिक शौचालयों के कारण हगंडारीमुक्त अभियान बर्बाद हो गया है। नवी मुंबई नगर निगम ने 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया; लेकिन आज भी नगर निगम क्षेत्र की कई मलिन बस्तियां सार्वजनिक शौचालय से दूर हैं। तुर्भे जिले के बोन्सारी गांव में महिलाओं और पुरुषों के लिए दस-दस सीटों का एक शौचालय है, लेकिन इस क्षेत्र की आबादी के कारण शौचालय की यह सुविधा मुश्किल हो रही है। इसलिए सुबह होते ही इस इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के बाहर नागरिकों की लंबी कतारें लग जाती हैं. इस जगह पर कई बार विवाद के मौके आ चुके हैं; और कभी-कभी, जब विवाद झगड़े में बदल जाते हैं, तो यह उन लोगों के लिए सुबह से ही इस स्थान पर लाइन में लगने का समय होता है जो काम के लिए घर से जल्दी निकलते हैं; चूंकि बच्चे और कुछ बुजुर्ग लोग खुले में अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए इलाके में दुर्गंध फैल गई है।

कुर्ला के बुल बाजार इलाके में वाडिया कॉलोनी रोड खराब हालत में... तत्काल मरम्मत की की जा रही है मांग !

चेंबूरः कुर्ला के बुल बाजार इलाके में वाडिया कॉलोनी में सड़क खराब हालत में है. जिससे नागरिकों को इस मार्ग पर चलने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. इसलिए क्षेत्रवासियों की ओर से इस सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की जा रही है. वाडिया एस्टेट नगर निगम के एल डिवीजन के बुल बाजार क्षेत्र में एक बड़ी संपत्ति है। यहां रहने वाले लोगों के बाहर निकलने की मुख्य सड़क पर काफी गड्ढे हैं। इसलिए, इस मार्ग से वाहन चलाना या पैदल चलना बहुत असुविधाजनक हो जाता है। इस सड़क पर बने गड्ढों को भरने की मांग को लेकर भाजपा उत्तर-मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष मोहन अंबेकर ने नगर निगम एल प्रभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा है।

कॉलोनी में सड़क पर नगर निगम और निजी स्कूल, अस्पताल, बाजार और शहरी बस्तियों का घना इलाका है। इसलिए वहां लगातार ट्रैफिक रहता है. यहां आरएमसी सीमेंट प्लांट है। इसलिए भारी वाहनों का आवागमन जारी है। इसलिए रहवासियों ने मांग की है कि नगर पालिका इस ओर ध्यान दे और इस सड़क की सीमेंट कंक्रीटिंग का काम शुरू कराए.

मुंबई में नए साल में वायु गुणवत्ता में सुधार...

मुंबईः मुंबई में पिछले दो महीने से खराब चल रही हवा की गुणवत्ता में अब कुछ सुधार हुआ है. अक्टूबर, नवंबर में अक्सर कुछ क्षेत्रों में खराब से बहुत खराब मौसम दर्ज किया गया। इस पृष्ठभूमि में, मुंबई नगर निगम ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया। इस बीच, नए साल की शुरूआत में मुंबई की वायु गुणवत्ता में सुधार होता दिख रहा है। मुंबई में प्रदूषण कम करने के लिए मुंबई नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है. इस बीच, धूल को नियंत्रित करने के लिए मुंबई शहर में उपकरणों के साथ अतिरिक्त जनशक्ति तैनात की गई है। नगर पालिका द्वारा सड़कों और फुटपाथों को पानी से धोया जा रहा है और फॉगर्स और एंटी-स्मॉग मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, धूल की मात्रा कम होने से मुंबई में हवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। पहले प्रतिदिन 500 से 600 किमी सड़कें धुलती थीं।

अब इसे बढ़ाकर एक हजार किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है. इस बीच, नगर पालिका ने इस काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पानी के टैंकर किराए पर लिए हैं। 25 अक्टूबर 2023 को घोषित गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर नगर पालिका बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इन दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्माण परियोजना स्थल के चारों तरफ हरा कपड़ा लगाना, पानी का निरंतर छिड़काव, निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को पूरी तरह से ढंकना और खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध जैसे सभी उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। नगर आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक आदेश जारी कर रहे हैं। इस बीच, अब तक इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले 2,995 निमार्णों को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही 603 निमार्णों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 868 निर्माण रोक दिये गये हैं. बिना तिरपाल वाले 104 निर्माण स्थलों से 2 लाख 10 हजार 800 रुपये का जुमार्ना वसूला गया है.

दो माह की तुलना में वायु गुणवत्ता में सुधार

प्रदूषण माप के लिए मुंबई में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 14 केंद्र, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के 9 केंद्र और नगर पालिका के 5 केंद्र स्थापित किए गए हैं। 1 नवंबर, 2023 को इन केंद्रों पर वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई। इस बीच, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के कार्यान्वयन के बाद वायु गुणवत्ता में अब सुधार हो रहा है। नए साल की शुरूआत में वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ और कोलाबा, कांदिवली, मुलुंड, शिव और वर्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगभग 50 प्रतिशत का सुधार हुआ।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com